

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

MSMES-प्रेरित विकास को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापार देयताओं की छूट प्रणाली (TREDS) का विस्तार

www.nextias.com

MSMES-प्रेरित विकास को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापार देयताओं की छूट प्रणाली (TReDS) का विस्तार

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026-27 ने व्यापार देयताओं की छूट प्रणाली (TReDS) के विस्तार हेतु प्रमुख सुधार प्रस्तावित किए हैं, जिनमें CPSEs द्वारा अनिवार्य उपयोग, CGTMSE के माध्यम से ऋण गारंटी, और MSME तरलता सुधारने के लिए GeM के साथ एकीकरण शामिल है।
- ये उपाय विश्व बैंक के 2025 वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (FSAP) की सिफारिशों के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य देयताओं के वित्तपोषण को सुदृढ़ करना और MSMEs को विलंबित भुगतानों से राहत देना है।

MSMEs एवं TReDS की आवश्यकता

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो रोजगार सृजन, निर्यात और औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान करते हैं।
 - किंतु MSMEs के सामने एक स्थायी चुनौती बड़ी कंपनियों से विलंबित भुगतान है, जो उनके कार्यशील पूंजी चक्र को बाधित करता है और विकास को सीमित करता है।
- TReDS को एक डिजिटल संस्थागत तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो MSMEs को उनकी देयताओं को तत्काल नकदी में परिवर्तित करने में सक्षम बनाता है।
- केंद्रीय बजट 2026-27 की हालिया नीतिगत पहलें और विश्व बैंक के FSAP 2025 की सिफारिशें इंगित करती हैं कि सरकार अब TReDS को केवल एक फिनटेक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि MSME वित्तपोषण के लिए एक संरचनात्मक सुधार के रूप में देख रही है।

TReDS को समझना

- TReDS एक RBI-नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो MSMEs की व्यापार देयताओं के वित्तपोषण को इनवॉइस डिस्काउंटिंग के माध्यम से सुगम बनाता है।
- इस प्लेटफॉर्म पर:
 - MSMEs अपने कॉर्पोरेट खरीदारों या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर उठाए गए इनवॉइस अपलोड करते हैं।
 - बैंक और NBFC इन इनवॉइस को वित्तपोषित करने के लिए बोली लगाते हैं।
 - देयता को छूट दी जाती है, जिससे MSMEs को इनवॉइस की नियत तिथि से पहले ही भुगतान प्राप्त हो जाता है।
- यह MSMEs की तरलता में सुधार करता है और पारंपरिक बैंक ऋण पर निर्भरता को कम करता है।

TReDS की वृद्धि एवं वर्तमान स्थिति

- शुरुआत से ही TReDS ने स्थिर विस्तार देखा है:
 - ₹7.5 लाख करोड़ से अधिक का वित्तपोषण TReDS के माध्यम से किया गया है।
 - वार्षिक लेन-देन मात्रा ₹2 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है।
 - हाल ही में मासिक थ्रूपुट ₹30,000 करोड़ से अधिक हो गया है।

- प्रगति के बावजूद, भारत में MSME देयताओं के विशाल पैमाने की तुलना में TReDS की पहुँच सीमित है।
- विलंबित भुगतान अभी भी MSMEs में नकदी प्रवाह व्यवधान और वित्तीय तनाव का प्रमुख कारण है।
 - इसलिए नीतिगत सुधारों का उद्देश्य प्लेटफॉर्म के दायरे और प्रभावशीलता का विस्तार करना है।

बजट 2026-27 में प्रमुख नीतिगत सुधार

- CPSEs द्वारा TReDS का अनिवार्य उपयोग: बजट प्रस्ताव करता है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSEs) MSMEs से की गई खरीद के निपटान हेतु TReDS का उपयोग करें। इससे MSME तरलता सुदृढ़ होगी और देयताओं के वित्तपोषण में पूर्वानुमेयता बढ़ेगी। इसके उद्देश्य:
 - बड़े खरीदारों और MSME आपूर्तिकर्ताओं के बीच शक्ति असमानता को कम करना।
 - समय पर इनवॉइस पुष्टि और भुगतान पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
 - निजी कॉर्पोरेट अपनाने के लिए मानक स्थापित करना।
- **CGTMSE के माध्यम से ऋण गारंटी तंत्र:** सरकार ने इनवॉइस डिस्काउंटिंग हेतु CGTMSE-समर्थित ऋण गारंटी का प्रस्ताव किया है। इससे छोटे उद्यमों के लिए वित्त तक पहुँच का विस्तार होगा और जोखिम साझा होगा। इसके निहितार्थ:
 - ऋणदाताओं के लिए अनुमानित क्रेडिट जोखिम कम होगा।
 - बैंकों और NBFCs की भागीदारी बढ़ेगी।
 - यह RBI के MSMEs के लिए बिना जमानत ऋण सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने के निर्णय का पूरक है।
- GeM के साथ एकीकरण: GeM को TReDS से जोड़ने से वित्तपोषकों को सत्यापित खरीद डेटा तक पहुँच मिलेगी। इससे लेन-देन लागत कम होगी और बाज़ार दक्षता बढ़ेगी। इसके प्रमुख लाभ:
 - सूचना असमानता कम होगी।
 - धोखाधड़ी जोखिम और ड्यू डिलिजेंस लागत घटेगी।
 - ऋण प्रसंस्करण समय तेज होगा।
- **TReDS-आधारित परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियों का विकास:** एक अन्य दूरदर्शी सुधार TReDS देयताओं का प्रतिभूतिकरण (Securitisation) है। इससे भारत के वित्तीय बाजारों की गहराई और वित्तीय लचीलापन बढ़ेगा। इसके प्रमुख लाभ:
 - वित्तपोषक पूल्ड देयताओं को बेचकर पूंजी का पुनर्चक्रण कर सकेंगे।
 - जोखिम व्यापक निवेशक आधार में वितरित होगा।
 - MSME देयताओं के वित्तपोषण को ऋण पूंजी बाज़ार से एकीकृत करेगा।

TReDS का व्यापक आर्थिक महत्व

- **कार्यशील पूंजी दक्षता में सुधार:** TReDS आपूर्ति श्रृंखलाओं में कार्यशील पूंजी दक्षता को बेहतर बनाता है, क्योंकि यह देयताओं के भुगतान को तीव्र करता है। जब MSMEs को भुगतान में विलंब होता है:
 - उत्पादन चक्र धीमा पड़ जाता है।
 - निवेश निर्णय स्थगित हो जाते हैं।
 - ऋण लागत बढ़ जाती है।

- वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करना: अनौपचारिक व्यापार ऋण नेटवर्क प्रायः अपारदर्शी और अनियमित रहते हैं, जो आर्थिक मंदी के दौरान वित्तीय तनाव को बढ़ा सकते हैं। TReDS इन जोखिमों को RBI-नियंत्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाता है, जिससे पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन में सुधार होता है।
- MSME विकास को समर्थन: समय पर देयताओं का वित्तपोषण MSMEs की लाभप्रदता, तरलता और परिचालन स्थिरता को बेहतर बनाता है। इस प्रकार, TReDS को सुदृढ़ करना समावेशी आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है।

चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

- TReDS की संभावनाओं के बावजूद कई बाधाएँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं:
 - MSMEs में कम जागरूकता।
 - बड़े निजी खरीदारों की सीमित भागीदारी।
 - इनवॉइस सत्यापन में परिचालन समस्याएँ।
 - भारत में अपर्याप्त फैक्ट्रिंग पारिस्थितिकी तंत्र।
- इन मुद्दों का समाधान करना देयताओं के वित्तपोषण की पूर्ण क्षमता को खोलने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

- व्यापार देयताओं की छूट प्रणाली (TReDS) भारत की वित्तीय संरचना में एक महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार का प्रतिनिधित्व करती है।
- विलंबित भुगतानों का समाधान कर और कार्यशील पूंजी तक पहुँच में सुधार कर, TReDS MSMEs की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करता है तथा आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को बढ़ाता है।
- बजट 2026-27 में घोषित नीतिगत उपाय, विश्व बैंक के FSAP की सिफारिशों के अनुरूप, एक अधिक संरचित, पारदर्शी और बाज़ार-आधारित देयताओं वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र की ओर संकेत करते हैं।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुँच में सुधार करने में व्यापार देयताओं की छूट प्रणाली (TReDS) की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसके प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

Source: BL

